



पेज 05

अब असली लड़ाई
शुरू होगी!

साप्ताहिक

शहर सत्ता

PRGI NO. CTHIN/25/A2378

सोमवार, 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2026

हम दिखाएंगे आईना...



पेज 08

सड़क पर मवेशी, हेल्पलाइन पर
शिकायतें और सिस्टम की सुस्ती!

वर्ष : 02 अंक : 32 पृष्ठ : 08 मूल्य : 5 रुपए

www.shaharsatta.com



पेज

04

खुरचन : स्मार्ट मीटर या महिषासुर...?

'समृद्धि' के नए द्वार खोलेगा 'होमस्टे'

पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिलाने में जुटी विष्णुदेव साय की सरकार

मुख्य संवाददाता/प्रदीप चंद्रवंशी
मोबाईल नंबर 7000681023

राज्य की अनुपम प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों, जनजातीय परंपराओं और पर्यटन की विविध संभावनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार के लिए छत्तीसगढ़ शासन जुट गया है। व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ विभिन्न राज्यों के पर्यटन विभागों, टूर ऑपरेटर्स और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के बीच संवाद एवं सहयोग को नई दिशा प्रदान की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड भी राष्ट्रीय बाजार पर छत्तीसगढ़ के पर्यटन, बस्तरिया आर्ट और प्राकृतिक सुंदरता के व्यापक प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। स्थानीय अर्थव्यवस्था, होटल व्यवसाय, परिवहन, हस्तशिल्प और पर्यटन से जुड़े अन्य सेवा क्षेत्रों को भी प्रोत्साहन मिलने की संभावनाएं बढ़ी हैं।



मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट में
छत्तीसगढ़ पर्यटन की
प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज

अंतरराष्ट्रीय पर्यटन सहयोग
से पर्यटन स्थलों का संयुक्त
प्रचार-प्रसार होगा

छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की
देशभर के टूर ऑपरेटर्स से
बढ़ने लगी है नजदीकी

छत्तीसगढ़ में समृद्ध
सांस्कृतिक विरासत और
पर्यटन की अपार संभावनाएं

आपसी समन्वय और
पर्यटकों की आवाजाही से
फलेगा-फूलेगा बस्तर आर्ट

राष्ट्रीय बाजारों के लिए बस्तर आर्ट की ब्रांडिंग और पैकेजिंग



बस्तर की सुप्रसिद्ध पारंपरिक ढोकरा (बेलमेटल) कला को अब राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने जा रही है। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा देश भर में ट्राइबल आर्टिजन क्लस्टरों को प्रीमियम क्लस्टर के रूप में विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत बस्तर के ढोकरा क्लस्टर चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मंत्रालय की मंशा चिलकुटी को एक समग्र मॉडल प्रीमियम क्लस्टर के रूप में स्थापित करने की है।

इसके तहत एक वर्षीय कार्ययोजना बनाकर एक ही एकीकृत परिसर में अत्याधुनिक ढोकरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मटेरियल स्टोर और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया जाएगा। साथ ही उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ उनकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग को आधुनिक बाजार के अनुरूप ढाला जाएगा। इस योजना के अंतर्गत बस्तर कला गुड़ी एक्सपेरियंस ज़ोन को एक सशक्त मार्केटिंग हब के रूप में भी विकसित किया जा रहा है, जिससे पारंपरिक शिल्पकारों को सीधे राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ा जा सकेगा।

विश्व प्रसिद्ध बस्तर का दशहरा

बारिश का मौसम बीतने के बाद से ही यहां हरे-भरे जंगल, पहाड़ और उनके उफनते पर्यटकों का मन मोह रहे हैं। इसलिए आज की तारीख में बस्तर भी देश के बेहतरीन पर्यटन स्थलों में एक साबित हो रहा है। हालांकि बस्तर का दशहरा बहुत पहले से प्रसिद्ध है, 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर के दशहरा में कुछ खास होने वाला है, लेकिन हाल के दिनों में इस अवसर पर जुटने वाले सैलानियों की संख्या में खासा इजाफा दर्ज किया गया है। इस वर्ष भी यहां का दशहरा देखने के लिए देश-विदेश से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। नवरात्रि और दशहरा के अलावा यहां दीपावली पर भी दुनिया भर से भारी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं।



होमस्टे के जरिए पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

होमस्टे नीति 2025-30 के माध्यम से ग्रामीण, जनजातीय और पर्यटन क्षेत्रों के परिवारों को अपने घरों को पर्यटन सुविधा में बदलकर अतिरिक्त आय और स्वरोजगार का अवसर मिलेगा। वहीं, पर्यटकों को स्थानीय खान-पान, कला, परंपरा, जनजातीय संस्कृति और जीवनशैली से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को भी नई पहचान मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा नए होमस्टे की स्थापना तथा मौजूदा मकानों के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता के साथ संचालकों को आतिथ्य, स्वच्छता और व्यवसाय संचालन का प्रशिक्षण देने का प्रावधान भी इस नीति में किया गया है। इससे मिलने वाला पैसा सीधे ग्रामीण परिवार, महिला स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय कारीगरों की जेब में जाएगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा मिलेगा। इस नीति से बस्तर और सरगुजा के अंचलों से लेकर मैदानी गांवों तक, होमस्टे के जरिए पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

गांव का युवा अपने ही क्षेत्र में पर्यटन उद्यमी बन सकेंगे

राज्य सरकार की नई उद्योग नीति में पर्यटन को सेवा उद्योग का दर्जा देने का कदम भी पर्यटन को गति देगा। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर, इको-टूरिज्म और होमस्टे विकसित करने वाले युवाओं और स्वयं सहायता समूहों को विशेष कैपिटल सब्सिडी, ब्याज अनुदान और सिंगल-विंडो क्लीयरेंस का लाभ मिलेगा। इसके अलावा ग्रामीण युवाओं को आतिथ्य, टूर गाइडिंग और डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देने का प्रावधान किया गया है, ताकि गांव का युवा अपने ही क्षेत्र में 'पर्यटन उद्यमी' बन सकें।

शहर सत्ता/रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पर्यटन विभाग छत्तीसगढ़ की पारंपरिक शिल्प कला के साथ ही प्राकृतिक अनछुए छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों छत्तीसगढ़ की वास्तविक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धि और प्राकृतिक विविधता से दुनिया को परिचित कराने में जुट गया है। छत्तीसगढ़ का बस्तर, पर्यटन के नक्शे पर अपनी पहचान, संस्कृति और प्रकृति की अनुपम छटा वाले पर्यटन क्षेत्र के रूप में जाना जा रहा है। वास्तव में बस्तर का वन क्षेत्र बेहद निराला है। प्रकृति की हरियाली और स्वच्छता पर्यटकों को आकर्षित करता है। धीरे-धीरे बस्तर न केवल विकास की धारा से जुड़ रहा है बल्कि पर्यटन के हिसाब से भी तेजी से बदल रहा है। यहां का खूबसूरत इलाका अपनी अनोखी आदिवासी संस्कृति, घने जंगलों की छटा सबका ध्यान खींच रहा है। साथ ही, यहां के लोगों का भावपूर्ण और अतिथि सत्कार भी दुनिया भर के पर्यटकों को लुभा रहा है।

जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए 'छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति' तैयार

छत्तीसगढ़ अब अपनी माटी की खुशबू, समृद्ध जनजातीय परंपराओं और गांवों के नैसर्गिक सौंदर्य के दम पर देश-दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर छाने को तैयार है। राज्य सरकार ने पर्यटन के विकास के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने के लिए नई औद्योगिक नीति (2024-2030) में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए 'छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति' तैयार की है। इसी कड़ी में अब ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'चेन्द्ररू राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार' की शुरुआत की गई है। इन तीनों निर्णयों से गांवों में रोजगार, आजीविका और सांस्कृतिक संरक्षण का नया अध्याय शुरू होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार का यह त्रिआयामी मॉडल पर्यटन को स्थानीय लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया को और अधिक मजबूत करेगा।



स्वच्छता दीदियों को मिलेगी नई वर्दी और सुरक्षा किट

शहर सत्ता/रायपुर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 की तैयारियों के बीच राज्य सरकार ने स्वच्छता दीदियों की वर्दी और सुरक्षा उपकरणों की खरीदी के लिए करीब 2.95 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। प्रदेश के 145 नगरीय निकायों में कार्यरत 7,992 स्वच्छता दीदियों को इसका लाभ मिलेगा। इस खरीदी के लिए प्रति कर्मी 3,700 रुपये की दर निर्धारित की गई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में नगरीय निकायों को निर्देश जारी किए हैं। सरकार की ओर से मंजूर की गई कुल राशि 2 करोड़ 95 लाख 70 हजार 400 रुपये है। इससे स्वच्छता के काम में लगी महिलाओं को जरूरी वर्दी और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। खास बात यह है कि इस खरीदी के लिए अलग से राशि जारी करने के बजाय नगरीय निकायों में उपलब्ध उपभोक्ता शुल्क यानी यूजर चार्ज की रकम का इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य शासन ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के नगरीय निकायों में स्वच्छता व्यवस्था से जुड़ी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में स्वच्छता दीदियों के लिए वर्दी और सुरक्षा उपकरण खरीदने की मंजूरी दी गई है। प्रदेश के 145 नगरीय निकायों में काम करने वाली 7,992 स्वच्छता दीदियों के लिए यह व्यवस्था की गई है। प्रत्येक कर्मी के लिए 3,700 रुपये की राशि तय की गई है।

पुलिस अफसर बनकर किया डिजिटल अरेस्ट, 22 लाख ठगे

शहर सत्ता/रायपुर। टेलीकॉम विभाग का अधिकारी और दिल्ली पुलिस का अफसर बनकर शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी एक व्यक्ति से 22 लाख की ठगी की गई। दरअसल पीड़ित को आरोपियों ने डर दिखाते हुए कहा कि उसे डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है। अलग-अलग बैंक खाते में आरोपियों द्वारा रुपए जमा करा लिए जाने के बाद उसे ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद उसने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। मामले में सरगुजा रेंज की साइबर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रार्थी ने गांधीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर खुद को टेलीकॉम विभाग का अधिकारी बताया। उसने प्रार्थी के नाम पर फर्जी सिम चालू होने और इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस में किए जाने की बात कही। इसके बाद दूसरे व्यक्ति ने वीडियो कॉल कर खुद को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताया और प्रार्थी के बैंक खाते में अवैध लेनदेन होने का डर दिखाया। आरोपियों ने प्रार्थी को डराकर उसकी जमा राशि का आरबीडीओ से सत्यापन कराने के नाम पर अलग-अलग बैंकों के खातों में 22 लाख ट्रांसफर करा लिए। मामले की जांच में ठगी (Fraud) की रकम का एक हिस्सा एमी के नर्मदापुरम निवासी साहिल सिंह के खाते में ट्रांसफर होने की जानकारी मिली।

छत्तीसगढ़ में शहरी परिवहन नए अध्याय की ओर 240 ई-बसों से आरामदायक, किफायती और प्रदूषणमुक्त सफर

शहर सत्ता/रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा में 240 इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर उतारने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की मौजूदगी में आज चारों नगर निगमों और चयनित एजेंसी चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड के बीच कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। इन चारों शहरों ने ई-बस संचालन शुरू करने की दिशा में आज बड़ा कदम बढ़ाया है। विभाग आगामी नवम्बर में बिलासपुर और भिलाई में 20-20 ई-बसों का संचालन प्रारंभ करने की तैयारी में है।

रायपुर में 100, दुर्ग-भिलाई और बिलासपुर में 50-50 तथा कोरबा में 40 बसें चलेंगी

योजना के प्रथम चरण में रायपुर में 100, दुर्ग-भिलाई में 50, बिलासपुर में 50 और कोरबा में 40 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना है। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार नवम्बर-

पीसीसी अध्यक्ष समेत 35 विधायक जाएंगे दिल्ली कल होने वाले प्रदर्शन में शामिल होंगे, जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक भी जुटेंगे

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज समेत पार्टी के सभी 35 विधायक और वरिष्ठ नेता आज दिल्ली रवाना होंगे। बैज शाम 5:50 बजे माना विमानतल पहुंचेंगे। यहां से वे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उनके साथ जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष, पूर्व विधायक और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी दिल्ली जाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का यह प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में कल होने वाले प्रदर्शन में शामिल होगा। प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस के नेताओं और विधायकों की भागीदारी रहेगी। इसके लिए पार्टी के अलग-अलग स्तर के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि दिल्ली पहुंचेंगे।

प्रदेश स्तर पर तैयारियां, दिल्ली में जुटेंगे नेता
दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं का एक साथ पहुंचना अहम माना जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के साथ विधायकों, जिला अध्यक्षों और पूर्व विधायकों की मौजूदगी से पार्टी की प्रदेश इकाई की भागीदारी रहेगी। हालांकि, प्रदर्शन का मुद्दा, आयोजन स्थल और कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

देश में अघोषित आपातकाल में तथाकथित लोकतंत्र सेनानी कहां छिपे हैं?

शहर सत्ता/रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात हैं। लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है और जनता के वोट की ताकत पर सवाल उठ रहे हैं। भाजपा शासित राज्यों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन रोकने के लिए बैरिकेडिंग, सड़कों पर कीलें लगाने, यातायात बाधित करने और इंटरनेट बंद करने जैसी कार्रवाई की शिकायतें सामने आ रही हैं। मीडिया की स्वतंत्रता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर भी हमला हो रहा है। ऐसे समय में लोकतंत्र की रक्षा का दावा करने वाले तथाकथित लोकतंत्र सेनानी आखिर कहां गायब हैं? क्या उनका लोकतंत्र प्रेम सिर्फ पेंशन लेने की तारीख तक ही जागता है?

प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि जब युवा अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं, बेटियां न्याय मांगती हैं और नागरिक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, तब उन्हें रोकने, गिरफ्तार करने और मुकदमों में

उलझाने की शिकायतें सामने आती हैं। लेकिन लोकतंत्र की दुहाई देने वाले तथाकथित सेनानी इन मुद्दों पर मौन साधे हुए हैं।

जो लोग लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर पेंशन लेते हैं, वे आज लोकतंत्र पर मंडरा रहे खतरे के खिलाफ आवाज उठाने से क्यों डर रहे हैं? प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि तथाकथित लोकतंत्र सेनानियों में से अनेक की राजनीतिक निष्ठा लोकतांत्रिक मूल्यों से अधिक संघ और भाजपा की विचारधारा के प्रति रही है। आज उनकी चुप्पी इस सवाल को और गंभीर बनाती है कि क्या उनका लोकतंत्र प्रेम सिद्धांतों पर आधारित है या राजनीतिक सुविधा पर। जनता के टेक्स से मिलने वाली पेंशन किसी को अपने लोकतांत्रिक दायित्वों से मुक्त नहीं करती। लोकतंत्र कोई तमगा नहीं, जिम्मेदारी है; और इस जिम्मेदारी की असली परीक्षा सत्ता के खिलाफ उठने वाली जनआवाज के समय होती है।

पहले बिजली बेचता था छत्तीसगढ़, भाजपा राज में खरीदना पड़ रहा - कांग्रेस भाजपा के राज में महंगी बिजली और बिजली कटौती हो रही

शहर सत्ता/रायपुर। भाजपा के शासन काल में बिजली उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि पहले छत्तीसगढ़ दूसरों को बिजली बेचता था आज खरीदना पड़ रहा है।

यह सरकार के कुप्रबंधन का परिणाम है। भाजपा सरकार महंगी बिजली बेच रही, स्मार्ट मीटर से लूट रही, अब बिजली उत्पादन भी नहीं कर पा रही है। उत्तरप्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों को

छत्तीसगढ़ बिजली बेचता था, आज छत्तीसगढ़ को बिजली खरीदने की नौबत आ गयी।

प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद विद्युत सरप्लस वाला छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कटौती का केंद्र बन गया है। कोई ऐसा दिन नहीं होता जब बिजली दो-चार घंटे के लिये बंद न हो, रात में तो बिजली की स्थिति तो और भयावह हो जाती है, घंटो बिजली गोल हो जाती है।

रायपुर में नारे लगाते हुए सड़क पर उतरीं लड़कियां

नारी सुरक्षा के लिए महिलाओं का मार्च, मोतीबाग चौक पर पुलिस ने रोका

शहर सत्ता/रायपुर। महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के विरोध में रविवार को रायपुर में महिलाएं और युवतियां सड़क पर उतरीं। महिला थाना चौक से शुरू हुए मार्च में नारी सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की मांग उठाई गई। प्रदर्शन में युवाओं ने भी हिस्सा लिया। हालांकि, पुलिस ने महिलाओं को मोतीबाग चौक के पास रोक दिया। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने 'नारी सुरक्षा हमारा अधिकार है, कोई एहसान नहीं' और 'एक कचौरी, दो समोसा, इन मर्दों का क्या भरोसा!' जैसे नारे लगाए।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि, महिलाओं की सुरक्षा केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसके लिए जमीन पर ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। स्कूल-कॉलेजों, सड़कों, सार्वजनिक परिवहन और कार्यस्थलों पर सुरक्षित माहौल होना जरूरी है। महिलाएं बिना डर के घर से बाहर निकल सकें, इसके लिए प्रशासन को प्रभावी कदम उठाने चाहिए। इस दौरान मुफ्त सैनिटरी पैड की उपलब्धता, छात्राओं की सुरक्षा, महिला पुलिस की गश्त, वर्क प्लेस पर महिलाओं के अधिकार, साइबर अपराधों पर सख्त कार्रवाई और पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने जैसी मांगें भी रखी गईं। इन मुद्दों को लेकर शासन के सामने

15 सूत्रीय मांग-पत्र सौंपा गया। प्रदर्शन में शामिल प्रियंका उपाध्याय ने कहा कि, महिलाओं की सुरक्षा कोई एहसान नहीं, बल्कि उनका अधिकार है। हर लड़की को बिना डर के घर से बाहर निकलने और सुरक्षित माहौल में जीने का अधिकार मिलना चाहिए। वहीं, पुनेश्वर लहरे ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई में युवाओं को भी आगे आना होगा। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी जायज मांगों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए।

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

संपादकीय

• सुकांत राजपूत

आम लोगों पर
बढ़ेगा कर्ज का बोझ

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की ओर से प्रमुख नीतिगत ब्याज दर यानी रेपो दर को 0.25 फीसद बढ़ाकर 5.50 फीसद करने का फैसला बढ़ती महंगाई और रुपए की विनिमय दर में गिरावट से बन रहे दबाव के कारण नीतिगत रुख में बदलाव का संकेत है। इसमें दोराय नहीं कि वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखना किसी भी केंद्रीय बैंक के लिए बड़ी चुनौती होती है।

जब महंगाई का दबाव बढ़ता है और कीमतों में लगातार वृद्धि होने लगती है, तब आरबीआइ मौद्रिक नीति के माध्यम से मांग को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। मगर इसका असर कर्ज, निवेश, रोजगार, उपभोग और आर्थिक विकास पर भी पड़ता है। रेपो दर बढ़ाने का सबसे ज्यादा असर कर्ज के लेन-देन पर पड़ेगा। आवास एवं वाहन समेत अन्य कर्ज महंगे हो सकते हैं और मौजूदा कर्जदारों की मासिक किस्त भी बढ़ सकती है। यानी पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को अब दोहरा संकट झेलना पड़ सकता है।

आरबीआइ का यह कदम हालांकि व्यापक रूप से अपेक्षित था, लेकिन नीतिगत रुख को तटस्थ से बदलकर 'सूझ-बूझ के साथ सख्त' करने का निर्णय कुछ हद तक चौंकाने वाला है। इससे निकट अवधि में रेपो दर में कटौती की संभावना लगभग समाप्त हो गई है। करीब चार साल में पहली बार रेपो दर में बढ़ोतरी की गई है और आगे भी यह क्रम जारी रह सकता है। रेपो दर वह ब्याज दर है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआइ से कर्ज लेते हैं। जब इस दर में इजाफा होता है, तो अमूमन बैंक भी लोगों के लिए ऋण पर ब्याज दर बढ़ा देते हैं।

आरबीआइ का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है और लोग इस वक्त घर, वाहन तथा कारोबार जैसी जरूरतों के लिए बैंक से कर्ज लेने की योजना बनाते हैं। ऐसे में कर्ज पर ब्याज दर बढ़ने से या तो उन्हें अपनी योजना टालनी पड़ेगी या फिर ज्यादा मासिक किस्त चुकानी पड़ेगी, जिसका असर उनके घरेलू बजट पर भी पड़ेगा। रेपो दर बढ़ाकर महंगाई को नियंत्रित करने का असर मांग में कमी के रूप में सामने आता है। यदि उपभोक्ता महंगे कर्ज के कारण खर्च कम करते हैं और कंपनियां निवेश को टालती हैं, तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग पर दबाव घट सकता है। मांग कम होने से उत्पादकों के लिए कीमतें बढ़ाना कठिन हो जाता है। मगर महंगाई हमेशा मांग के कारण ही नहीं बढ़ती।

खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि, खराब मानसून, आपूर्ति बाधाएं, कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उछाल या भू-राजनीतिक संकट जैसी परिस्थितियां भी महंगाई का कारण बन सकती हैं। ऐसे में रेपो दर बढ़ाने का प्रभाव सीमित हो सकता है। यदि खाद्य वस्तुओं के मूल्य आपूर्ति की कमी के कारण बढ़ रहे हों, तो महंगे कर्ज से उनकी कीमतें सीधे कम नहीं की जा सकतीं। इसके लिए मौद्रिक नीति के साथ आपूर्ति पक्ष के उपाय भी जरूरी होते हैं।

रेपो दर बढ़ने का प्रभाव आर्थिक विकास पर भी पड़ता है। महंगे कर्ज से कंपनियों की निवेश योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं और छोटे एवं मध्यम उद्यमों के लिए कार्यशील पूंजी जुटाना कठिन हो सकता है। जाहिर है, रेपो दर में बढ़ोतरी तभी प्रभावी हो सकती है, जब इसे सरकार के आपूर्ति संबंधी उपायों, उत्पादन बढ़ाने की नीतियों और रोजगार सृजन के प्रयासों का साथ मिले।

संपादकीय
स्मार्ट मीटर या महिषासुर...?

सरकारी लूट का डिजिटल अवतार



महिषासुर के बारे में सुना था कि वह देवताओं और मनुष्यों को परेशान करता था। अब स्मार्ट मीटर आ गया है। फर्क इतना है कि महिषासुर से मुक्ति के लिए माँ दुर्गा को आना पड़ा था, और स्मार्ट मीटर से मुक्ति के लिए फिलहाल लोगों को बिजली विभाग के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

स्मार्ट मीटर लगने के बाद आदमी बिजली का बिल देखकर खुद भी जलने लगा है। बिल चार गुना! मानो घर में पंखा, बल्ब और कूलर नहीं, बिजली का कोई राक्षस बैठा हो, जो रात-दिन यूनिते निगल रहा हो। और इस राक्षस की खूबी देखिए—इसे भूख लगती है तो जेब पर हमला करता है, और पैसा न मिले तो घर का अंधेरा निगलने के बजाय रोशनी ही निगल जाता है। एक महीने का बिल नहीं भरा, आटोमेटिक मशीन ने बिजली काट दी! न कोई मानवीय संवेदना, न परेशानी समझने की जरूरत। मशीन को क्या मालूम कि घर में बूढ़े माँ-बाप हैं, बच्चे पढ़ते हैं, मजदूर की मजदूरी अटकी है या परिवार पहले से महंगाई के महिषासुर से लड़ रहा है!

व्यवस्था कहती है—मीटर स्मार्ट है।

जनता पूछती है—साहब, मीटर स्मार्ट है तो बिल चार गुना क्यों? और अगर बिल सही है तो हिसाब समझाने में व्यवस्था की बुद्धि कहाँ चली जाती है?

महिषासुर कम-से-कम पौराणिक कथा में था। यह वाला घर-घर में लगा दिया गया है। उसके हाथ में हथियार था, इसके हाथ में डिजिटल तकनीक है। वह युद्ध करके डराता था, यह बिल भेजकर डराता है। वह प्रजा पर अत्याचार करता था, यह गरीब की जेब पर सीधा प्रहार करता दिखाई देता है। लेकिन असली सवाल मीटर का नहीं, उस व्यवस्था का है जो तकनीक को जनता की सुविधा से अधिक वसूली का औजार बना दे।

स्मार्ट मीटर लगाइए, लेकिन बिल भी समझदार बनाइए। तकनीक लाइए, लेकिन इंसानियत को बिजली काटकर बाहर मत कीजिए। क्योंकि जनता को ऐसी स्मार्ट व्यवस्था नहीं चाहिए, जिसमें मीटर चौबीस घंटे जागता रहे और गरीब का घर चौबीस घंटे बिल की चिंता में सो न सके।

जनता अब पूछने लगी है कि महिषासुर का वध तो देवी ने किया था, लेकिन इस नए डिजिटल महिषासुर से हमें कौन बचाएगा?

हेरानी की बात है कि छत्तीसगढ़ बिजली पैदा करने में सरप्लस है, लेकिन अपने ही लोगों को सस्ती बिजली देने में कंगाल! कोयला हमारा, बिजलीघर हमारे, उत्पादन हमारा—मगर बिजली के बिल भरते वक्त जनता की जेब पर ही करंट क्यों लगता है? छत्तीसगढ़ में बिजली पैदा जनता के लिए होती है और महँगी जनता की ही किस्मत में लिखी जाती है!

गांव का किसान हो या शहर का मध्यमवर्गीय परिवार, दिहाड़ी मजदूर हो या छोटा दुकानदार—आज हर कोई स्मार्ट मीटर के नाम पर आ रहे बिजली बिलों से हलाकान है। कहीं बिल कई गुना उछलकर गरीब की कमर तोड़ रहा है, तो कहीं पर्याप्त सूचना दिए बिना बिजली काटकर लोगों को अंधेरे में धकेल दिया जा रहा है। विडंबना देखिए, जिस तकनीक का दावा बिजली व्यवस्था को स्मार्ट बनाने के लिए किया गया था, वही आम आदमी के लिए मुसीबत का मीटर बनती जा रही है। सवाल यह है कि स्मार्ट मीटर बिजली कंपनियों की कमाई बढ़ाने के लिए हैं या जनता की परेशानी घटाने के लिए? अगर तकनीक इतनी ही स्मार्ट है, तो फिर जनता की जेब पर पड़ने वाली यह मार और बिना चेतावनी गुल होती बिजली किसकी नाकामी है? मीटर स्मार्ट हो गए, व्यवस्था डिजिटल हो गई, लेकिन जनता के प्रति जवाबदेही आज भी अंधेरे में है!

हलाकान लोग गुहार लगा रहे हैं, "हे माँ दुर्गे! इस महिषासुर रूपी सरकारी लूट के डिजिटल अवतार स्मार्ट मीटर से मुक्ति दिलाओ। बिजली का बिल देखकर दिल बैठ जाता है, शिकायत लेकर विभाग जाओ तो चक्कर लगाते-लगाते चप्पल घिस जाती है, और सुनवाई न हो तो अंधेरे में रात बितानी पड़ती है!"

जाहिर है कि बिजली का सरप्लस तभी सार्थक है, जब जनता का बिल कम हो, किसान की लागत घटे, कारोबार को ताकत मिले और घर रोशन रहें। वरना बिजली उत्पादन के आंकड़े भले चमकते रहें, जनता की जिंदगी में उनका उजाला कहाँ है?

छत्तीसगढ़ में गति पकड़ता राजस्व न्याय

विष्णु प्रसाद वर्मा

सहायक संचालक

छत्तीसगढ़ में राजस्व प्रशासन को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और जनोन्मुख बनाने की दिशा में राजस्व न्यायालयों के प्रदर्शन में एक नया अध्याय जुड़ गया है। दूरस्थ अंचलों से लेकर बड़े शहरों तक भूमि, नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और स्वामित्व जैसे आम नागरिकों के जीवन से जुड़े अत्यंत संवेदनशील मामलों को समयबद्ध सीमा में सुलझाने के लिए प्रशासनिक प्राथमिकताओं में अभूतपूर्व बदलाव आया है। राज्यभर के राजस्व न्यायालयों में दर्ज कुल 4,67,415 प्रकरणों में से रिकॉर्ड 3,80,224 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण कर लिया गया है। इस प्रकार संपूर्ण राज्य में मामलों के निराकरण की दर 81.35 प्रतिशत तक पहुँच चुकी है, जबकि शेष 87,191 प्रकरणों के निपटारे के लिए भी लक्षित एवं सुव्यवस्थित प्रयास जारी हैं।

कोर्ट-कचहरी के चक्करों से मुक्ति, समय और धन की बचत

राजस्व मामलों का शीघ्र निपटारा केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव ज़मीन और आजीविका से जुड़े नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है। कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने से मुक्ति मिलने के साथ-साथ आम जन के समय और संसाधनों की बचत हो रही है, जिससे राज्य में पारदर्शी एवं नागरिक-केंद्रित व्यवस्था सुदृढ़ हुई है।

दूरस्थ एवं आदिवासी अंचलों का शानदार प्रदर्शन

राजस्व न्याय की इस तीव्र गति में सबसे प्रेरणादायक तस्वीर राज्य के दूरस्थ एवं आदिवासी बहुल जिलों से सामने आई है, जहाँ प्रशासनिक पहुँच और त्वरित निर्णय क्षमता मिसाल बनी है। सुकमा जिला 92.70 प्रतिशत निराकरण दर के साथ पूरे प्रदेश में शीर्ष पर है, जहाँ 7,224 मामलों में से 6,697 का निपटारा किया गया है। इसी तरह नारायणपुर में 92.28 प्रतिशत (5,780 में से 5,334 प्रकरण), दंतेवाड़ा में 91.50 प्रतिशत (5,614 में से 5,137 प्रकरण) और बीजापुर में 89.67 प्रतिशत की उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है।

बड़े जिलों में भी तेजी से सुलझ रहे ज़मीन-जायदाद के मामले

भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद दूरदराज के क्षेत्रों में मिली यह सफलता प्रशासनिक तंत्र की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वहीं, राज्य के अधिक केस भार वाले बड़े जिलों में भी प्रकरणों के निपटारे का सिलसिला पूरी तेजी से चल रहा है। बस्तर में 17,600 में से 15,745 प्रकरण, बलौदाबाजार-भाटापारा में 20,905 में से 18,494 प्रकरण, राजधानी रायपुर में 34,226 में से 29,824 प्रकरण, बिलासपुर में 29,495 में से 24,539 प्रकरण, जांजगीर-चांपा में 19,132 में से 16,109 प्रकरण तथा कोरबा में 19,705 में से 15,747 मामलों को हल कर नागरिकों को राहत दी गई है।

'ई-धरती' और आधुनिक सर्वेक्षण से संवरते भू-अभिलेख

राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण के साथ-साथ राज्य सरकार 'ई-धरती' योजना और आधुनिक भू-सर्वेक्षण तकनीकों के ज़रिए भू-अभिलेखों के सुदृढ़ीकरण पर भी व्यापक काम कर रही है। राज्य में 431

वन ग्राम से परिवर्तित राजस्व ग्राम और 596 असर्वेक्षित या मसाहती ग्रामों को मिलाकर कुल 1,027 ग्रामों का सर्वे हेतु चिन्हांकन किया गया है। इनमें से 284 ग्रामों का सर्वेक्षण कार्य पूरा करके डाटा 'भुइयों पोर्टल' पर अपलोड भी कर दिया गया है, जबकि 196 ग्रामों में अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया चल रही है।

अबूझमाड़ में ऐतिहासिक पहल और डिजिटल नक्शों का निर्माण

अति-संवेदनशील अबूझमाड़ क्षेत्र और नारायणपुर जिले में भी ग्राम सर्वेक्षण की शुरुआत एक ऐतिहासिक पहल है, जहाँ 6 ग्रामों का अंतिम प्रकाशन पूर्ण कर अभिलेखों एवं नक्शों को 'भुइयों' और 'भू-नक्शा' सॉफ्टवेयर पर अपलोड कर दिया गया है तथा 59 अन्य ग्रामों में अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया गतिमान है। इसके अतिरिक्त, ई-धरती योजना के तहत बंदोबस्त नुटियों को सुधारने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में कोडगांव जिले को 1.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है। नगरीय निकायों के कैडेस्ट्रल नक्शों को 1:500 के सूक्ष्म पैमाने पर बदलने की दिशा में भी काम तेजी से जारी है,

जिसके तहत 22 जिलों के 396 गांवों को नए पैमाने के नक्शे प्रदान कर दिए गए हैं, जबकि नज़ूल व परिवर्तित अभिलेखों के डिजिटाइजेशन का कार्य भी अंतिम चरणों में है। वर्ष 2025-26 के लिए पात्र हितग्राहियों के सत्यापन एवं e-KYC की प्रक्रिया को भी प्रगति पर रखा गया है।

वर्षों पुराने लंबित मामलों के लिए वैज्ञानिक रणनीति

न्यायालयीन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए लंबित 87,191 प्रकरणों का समयावधि के अनुसार वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है। वर्तमान में 0 से 6 माह की अवधि के 51,401 मामले लंबित हैं, जबकि 6 माह से 1 वर्ष के 13,218 मामले, 1 से 3 वर्ष के 15,918 मामले, 3 से 5 वर्ष के 3,903 मामले और 5 वर्ष से अधिक अवधि के 2,751 प्रकरण लंबित सूची में हैं। इस वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य वर्षों पुराने प्रकरणों को चिन्हित कर उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हल करना है, ताकि लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवादों का स्थायी अंत हो सके।

राज्यभर में 80% से अधिक सफलता दर और प्रभावी समीक्षा

प्रदेश के अन्य जिलों में भी 80 प्रतिशत या उससे अधिक निराकरण दर दर्ज की गई है, जिनमें राजनांदगांव 83.45 प्रतिशत, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई 83.42, कोरिया 81.87, सारंगढ़-बिलाईगढ़ 81.84, धमतरी 81.65, बेमेतरा 81, जशपुर 80.67, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी 80.38, कबीरधाम 80.23 और कांकर 80.21 प्रतिशत शामिल हैं। इसके अलावा सरगुजा, महासमुंद, रायगढ़, सूरजपुर, गरियाबंद, गौरला-पेंड्रा-मरवाही, दुर्ग, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और बलरामपुर-रामानुजगंज जैसे जिलों में भी निरंतर समीक्षा बैठकों, डिजिटल ट्रेकिंग और समयबद्ध सुनवाई के माध्यम से मामलों के निपटारे की प्रक्रिया को गति दी जा रही है।

पारदर्शी और त्वरित सुशासन की ओर बढ़ते कदम

डिजिटल गवर्नेंस, आधुनिक सर्वेक्षण तकनीकों और नियमित मॉनिटरिंग के इस सशक्त संगम से छत्तीसगढ़ का राजस्व प्रशासन आज अधिक त्वरित, पारदर्शी और पूरी तरह जन-कल्याणकारी स्वरूप धारण कर चुका है।



अंग्रेज देखेंगे INS त्रिशूल का जलवा, युद्धाभ्यास के लिए ब्रिटेन पहुंची भारतीय नेवी

नई दिल्ली। होर्मुज स्ट्रेट में कुवैत के झंडे वाले एक कूड ऑयल टैंकर पर प्रोजेक्टाइल से हमला होने के बाद उसमें सवार पांच भारतीय नागरिकों को सुरक्षित तट पर पहुंचा दिया गया. ओमान में भारतीय दूतावास ने शुक्रवार को बताया कि उसने बचाव अभियान के दौरान पांचों भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए समन्वय किया. दूतावास ने इस अभियान में लगातार सहयोग और मदद के लिए ओमानी अधिकारियों का आभार भी जताया. दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि टैंकर MT Kazimah III को होर्मुज स्ट्रेट में एक प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया था. इसके बाद टैंकर में सवार पांच भारतीय नागरिकों को सुरक्षित तट पर पहुंचाया गया. दूतावास ने कहा कि ओमानी अधिकारियों के सहयोग से यह बचाव अभियान पूरा किया गया.MT Kazimah III एक कूड ऑयल टैंकर है, जो फिलहाल कुवैत के झंडे के तहत संचालित हो रहा है. यह टैंकर टोगो के लोमे बंदरगाह की ओर जा रहा था. प्रोजेक्टाइल लगने के बाद जहाज पर मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भारतीय मिशन ने तत्काल बचाव अभियान का समन्वय किया.

पाकिस्तान में ईशनिंदा पर ईसाई परिवार पर हमला

नई दिल्ली। पाकिस्तान में ईशनिंदा करने के बाद से ईसाई परिवार डरे हुए हैं. ईशनिंदा के आरोपों के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों की भीड़ ने एक ईसाई व्यक्ति के घर और दवाओं की दुकान में आग लगा दी. इस आग लगने के बाद वहां डर का माहौल है और हमले की आशंका के चलते 35 से अधिक ईसाई परिवार अपना घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए. पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी. पुलिस के अनुसार, यह घटना बृहस्पतिवार को लाहौर से लगभग 50 किलोमीटर दूर शेखुपुरा जिले के घड़ियाल कलां गांव में हुई. यह बवाल 40 वर्षीय कामरान गुल मसीह पर सोशल मीडिया पर ईशनिंदा से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री साझा करने के आरोप लगने के बाद शुरू हुआ. पुलिस अधिकारी जुबैर अब्बास ने बताया कि मसीह को गिरफ्तार कर लिया गया है और उग्र भीड़ के हमले से बचाने के लिए उसे सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है. अब्बास ने बताया कि उग्र भीड़ ने उसके घर को आग के हवाले कर दिया और बाद में उसकी फार्मसी को भी फूंक दिया.भीड़ के आने की खबर फैलते ही स्थानीय ईसाई समुदाय में दहशत फैल गई और हमले के डर से 35 से अधिक परिवार अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए.

बंगाल और ओडिशा में GPIL के कई ठिकानों पर ED रेड

नई दिल्ली।ED के कोलकाता ज़ोनल ऑफिस- II ने PMLA 2002 के तहत 5 अक्टूबर 2026 को पश्चिम बंगाल और ओडिशा में M/s गुप्ता पावर इंफ़्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (GPIL), उससे जुड़ी कंपनियों और उसके मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के 9 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया. यह कार्रवाई GPIL द्वारा किए गए बैंक फ्रॉड की जांच के सिलसिले में की गई. तलाशी के दौरान PMLA, 2002 के प्रावधानों के तहत कई आपत्तिजनक दस्तावेज/डिवाइस/रिकॉर्ड मिले और ज़ब्त किए गए. PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत GPIL से जुड़े कुल 139 बैंक अकाउंट और GPIL व उससे जुड़े व्यक्तियों के नाम पर मौजूद कई म्यूचुअल फंड और शेयर फ्रीज कर दिए गए हैं. इसके अलावा 3 महंगी कारें भी फ्रीज की गई हैं।

देश-विदेश

सोमवार, 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2026

05

अब असली लड़ाई शुरू होगी!

CJP ने PM मोदी और अमित शाह पर बोला तीखा हमला



नई दिल्ली। मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने अपना आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। रविवार को सीजेपी नेताओं ने दिल्ली के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के बावजूद वे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। यह लड़ाई अब सचमुच शुरू हो गई है। इसे पूरे देश में और बढ़ाया जाएगा।

इस बीच, CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके, सीजेपी के सह-संयोजक और प्रवक्ता आशुतोष रांका और सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास को करीब

24 घंटे बाद रविवार सुबह रिहा कर दिया गया। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, अदालत ने उन्हें इस शर्त पर जमानत दी कि वे एक साल तक शांति भंग करने वाली किसी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिजीत दिपके शामिल नहीं हो सके क्योंकि वह आज अपनी दादी के निधन के चलते घर लौट गए हैं।

'ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक घर नहीं लौटेंगे'

सीजेपी ने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर दोबारा जंतर-मंतर पर मार्च निकालेंगे और वहीं डटे रहेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने जनता से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की।दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर सीजेपी नेताओं ने नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलनकारियों को हिरासत में लिया गया और उनके साथ मारपीट की गई। पार्टी नेताओं ने इतनी सख्त सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी आलोचना की। CJP नेता आशुतोष रांका ने आरोप लगाया कि पिछले 72 घंटों में देश में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं होगा। दिल्ली में जिस तरह की परिस्थितियां बनीं, उससे देश की छवि को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने दावा किया कि देशभर में हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग किया गया।



क्या अब प्रदर्शन नहीं करेंगे CJP के नेता?

सीजेपी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बॉन्ड से जुड़े दावों पर कहा है कि सीजेपी के किसी भी नेता ने ऐसा कोई बॉन्ड नहीं साइन किया है, जिसमें कहा गया हो कि वे अब और विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे. बॉन्ड में शांति भंग न करने की बात कही गई है. लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होना, एक संवैधानिक अधिकार है. इससे शांति भंग नहीं होती है. आज सुबह ही दिल्ली पुलिस ने इन्हें मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद सीजेपी के सौरव दास, अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका को डिटेन्शन से छोड़ दिया गया है. उन्होंने कोर्ट में शांति भंग न करने से जुड़ा एक बॉन्ड भरा है. इसपर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि भविष्य में अब ये लोग अब आंदोलन या प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे. लेकिन अब इन आरोपों पर सीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. इसी से जुड़ एक्स पर एक पोस्ट को रिपोस्ट करते सीजेपी ने खंडन किया है. इधर, डिटेन्शन के बाद बाहर आए सौरव दीपके, आशुतोष रांका, रत्ना सिंह समेत कई लोगों ने प्रेस को संबोधित किया. इन्होंने बताया कि कैसे उन्हें एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया. इस दौरान आशुतोष से लेकर सौरव दास ने सरकार पर और दिल्ली पुलिस पर जमकर निशाना साधा. साथ ही सवाल उठाए कि देश की अदालतों ने स्वतः संज्ञान जैसे एक्शन क्यों नहीं लिए. इस दौरान सौरव ने मौलिक अधिकारों के हनन को लेकर भी सवाल उठाए हैं।

कोर्ट के फैसले का उल्लंघन, दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर मेट्रो स्टेशन बंद करने और आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में रविवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि सभी बैरिकेड हटाए जाने चाहिए, जब तक कि उन्हें बनाए रखना बेहद जरूरी न हो। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लोगों की स्वतंत्र आवाजाही सामान्य की जानी चाहिए, हालांकि कानून-व्यवस्था की स्थिति में जरूरी नियम किया जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में पीठ ने सुनवाई के दौरान मेट्रो के सामान्य संचालन की भी बात की। पीठ ने कहा कि दिल्ली में कहीं भी इंटरनेट बंद नहीं किए जाए।



बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी वकील शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान आई। याचिका में अदालत के 9 अक्टूबर के आदेश का हवाला दिया गया था। उस आदेश में सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने और ट्रेनों को रद्द किए जाने से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई थी।जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि लोगों को विरोध-प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार कानून के दायरे में होना चाहिए। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि आपको प्रदर्शन करने का अधिकार है, इसमें कोई विवाद नहीं है।

24 घंटे बाद हिरासत से छूटे ध्रुव राठी

नई दिल्ली।यूट्यूबर ध्रुव राठी को दिल्ली पुलिस ने देर रात हिरासत से छोड़ दिया है. दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक अगर ध्रुव प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए जंतर-मंतर जाएंगे तो पुलिस उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है. ध्रुव 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए थे. प्रोटेस्ट से पहले दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया था. ध्रुव राठी उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें 10 अक्टूबर को प्रोटेस्ट से पहले हिरासत में लिया गया था.

उन्हें जंतर-मंतर पर आने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम पुलिस की मदद से उनके घर से हिरासत में लिया था. ध्रुव इससे पहले बेंगलुरु में सीजेपी के प्रोटेस्ट में नजर आए थे. बेंगलुरु प्रोटेस्ट में



उनके साथ एक्टर प्रकाश राज और सीजेपी नेता अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका भी थेप्रोटेस्ट से एक दिन पहले ध्रुव राठी ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था. जिसमें उनके पीछे इंडिया गेट नजर आ रहा था. इस वीडियो में उन्होंने लोगो से आंदोलन में शामिल होने के लिए कहा था. ध्रुव का ये वीडियो

देखकर सभी को पता चल गया था कि वो दिल्ली आ चुके हैं.ध्रुव राठी के अलावा सीजेपी नेता अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था. उन्हें प्लेन से ही हिरासत में ले लिया था. सीजेपी नेताओं अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी.

ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी सांसद! रूसी तेल बिल को रोकने की तैयारी

नई दिल्ली। रिपब्लिकन सांसद ब्रायन फिट्जपैट्रिक ने घोषणा की है कि वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रूसी डीजल पर से प्रतिबंध हटाने के फैसले को रोकने के लिए एक द्विदलीय विधेयक पेश करेंगे. ट्रम्प ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के बाद यह कदम उठाया था. फिट्जपैट्रिक के इस कदम का रिपब्लिकन सांसद डॉन बेकन ने सपोर्ट किया है और वो इस विधेयक के सह-प्रायोजक बनने के लिए तैयार हो गए हैं. हालांकि, यह कदम काफी हद तक प्रतीकात्मक माना जा रहा है क्योंकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की वर्तमान मियाद जनवरी में खत्म हो रही है और उनके पास इसे पास कराने के लिए केवल कुछ ही महीनों का समय है.कांग्रेस की यूक्रेन कॉकस के सह-अध्यक्ष फिट्जपैट्रिक ने सोशल मीडिया पर लिखा, "हम रूसी तेल की सभी खरीदारियों को रोकने के लिए एक द्विदलीय कानून पेश करेंगे. इसे 'रोनाल्ड रीगन पीस थ्रू स्ट्रैंथ एक्ट' कहा जाएगा और इसे संसद में भारी समर्थन से पास कराया जाएगा. बेकन ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि संसद को इसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाना होगा. हाल ही में पुतिन से बातचीत के बाद, ट्रंप ने घोषणा की थी कि उन्होंने अमेरिका और वैश्विक बाजार में तुरंत 3,00,000 टन डीजल की आपूर्ति के लिए रूस के साथ समझौता किया है।

विजय ने पीएम मोदी के सामने रखी कई शर्तें

नई दिल्ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राज्य की बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा और जल संसाधनों से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए। उन्होंने समग्र शिक्षा अभियान (S S A) के तहत केंद्र सरकार से तमिलनाडु के हिस्से के 5,110 करोड़ रुपये बिना किसी शर्त के जारी करने की अपील की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कोयंबटूर और मदुरै में मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी देने तथा तमिलनाडु के होसुर से कर्नाटक के बोम्मासंद्रा तक इंटरस्टेट मेट्रो रेल लाइन बनाने का प्रस्ताव भी रखा।

मुख्यमंत्री विजय ने तमिलनाडु की जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के उद्घाटन के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि राज्य में विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास और आधारशिला रखे जाने से विकास कार्यों को गति मिलेगी। सीएम विजय ने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान (SSA) के तहत केंद्र सरकार की ओर से तमिलनाडु को मिलने



वाले 5,110 करोड़ रुपये बकाया हैं। उन्होंने केंद्र से यह राशि बिना किसी शर्त के जारी करने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट 2026 में बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई के बीच दो हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र को लाभ मिलेगा और संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी। इस दौरान सीएम विजय ने गोदावरी-कावेरी नदी जोड़ी परियोजना को दक्षिणी राज्यों में जल संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर बताया. उन्होंने केंद्र सरकार से इस परियोजना को प्राथमिकता देने और राष्ट्रीय परियोजना के रूप में अर्थारिटी ने रविवार सुबह एक बयान में इसकी जानकारी दी है. मरने वालों 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमेरिका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सूडान और फिलिस्तीन से 1-1 नागरिक शामिल थे. धमाके के वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं. इस धमाके से दो दिन पहले भी एयरपोर्ट पर अटैक हुआ था जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी.सऊदी के अधिकारियों के बयान में बताया गया है कि कुछ घायलों की हालत गंभीर है. सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है. घायलों को कुबुलेंस और हेलिकॉप्टर से लाया गया है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया है कि घायलों से अस्पताल भर गए थे।

सऊदी के रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले में 12 की मौत, 309 घायल

नई दिल्ली।शनिवार को सऊदी अरब के रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा धमाका हुआ है. इस घटना में कई लोगों की मौत हो गई है और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. सऊदी अधिकारियों ने मरने वालों और घायलों की जानकारी दी है.धमाका यमन के ईरान समर्थित हूति विद्रोहियों के ग्रुप की ओर से दागी गई मिसाइल हमलों में तेजी के बीच हुआ. सऊदी अधिकारियों का कहना है कि रियाद एयरपोर्ट पर हुए हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 लोग घायल हो गए. सऊदी की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने रविवार सुबह एक बयान में इसकी जानकारी दी है. मरने वालों 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमेरिका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सूडान और फिलिस्तीन से 1-1 नागरिक शामिल थे. धमाके के वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं. इस धमाके से दो दिन पहले भी एयरपोर्ट पर अटैक हुआ था जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी.सऊदी के अधिकारियों के बयान में बताया गया है कि कुछ घायलों की हालत गंभीर है. सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है. घायलों को कुबुलेंस और हेलिकॉप्टर से लाया गया है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया है कि घायलों से अस्पताल भर गए थे।

नेपाल में फिर तबाही! बूढ़ी गंडकी में आई बाढ़

काठमांडू। नेपाल में एक बार फिर से कुदरत ने करवट ली है, जो कि नेपाल के लोगों के लिए बड़ी आफत बनती दिख रही है. नेपाल के गोरखा जिले से बहने वाली गंडकी नदी में पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है, गंडकी नदी में बढ़ रहा यह उफान लोगों के लिए तबाही बनकर उनके घरों में घुस रहा है. बूढ़ी गंडकी नदी में आई बाढ़ की वजह से गोरखा जिले में कम से कम 10 लोग लापता हो गए, 6 पुल बह गए और करीब 35 घर तबाह हो गए. अधिकारियों ने बचाव और राहत काम के लिए सेना के जवानों और हेलीकॉप्टरों को तैनात किया है, साथ ही नदी किनारे रहने वालों को तुरंत दूसरी जगह जाने की चेतावनी दी है.

इस बाढ़ में कई पुल बाढ़ के पानी से तबाह हो गए. बूढ़ी गंडकी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कैप बिल्डिंग तबाह हो गई. नदी के किनारे रहने वालों के लिए अलर्ट जारी हुआ. फिलहाल नेपाल पुलिस की ओर से लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है. बूढ़ी गंडकी नदी के तटवर्ती इलाकों में बसे लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया.नदी में बढ़ रहे पानी के स्तर को देख कर लोगों में नुकसान का डर एक बार फिर से नजर आने लगा है, कई इलाकों में बाढ़ का खतरा लगातार पैदा हो गया है. लोग डरे, सहमे हुए हैं और सुरक्षित जगहों की तलाश कर रहे हैं. प्रशासन लगातार आसपास के इलाकों में सूचना जारी करके और माइक से अनाउन्मेन्ट करके लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रहा है.



प्रधानमंत्री बालेन शाह ने कहा है कि आर्मी की एक टुकड़ी को हवाई रास्ते से हालातों पर काबू करने और लोगों की रक्षा के लिए भेजा जा रहा है. साथ ही गृह मंत्री सुडान गुरुंग ने बताया कि बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए हेलीकॉप्टर टीमों समेत सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और घाट्टेखोला में कुछ घरों में बाढ़ का मटमैला पानी घुस गया है. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, गुरुंग ने चुमनुबरी ग्रामीण नगर पालिका के वार्ड 3 में न्याकचेट और फिल्म बाजार को जोड़ने वाले पुल के नष्ट होने पर चिंता जताई।





पूरी तरह से बंद होंगी पेट्रोल वाली बाइक टैक्सी

मुंबई। अगर आप महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी से सफर करते हैं या इस सेवा के जरिए अपनी कमाई करते हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है. राज्य में बाइक टैक्सी चलाने वाले ऑपरेटरों को पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक बाइक अपनाने के लिए जुलाई 2027 तक का समय दिया गया है. इस बदलाव का खास मकसद शहरों में बढ़ने वाले प्रदूषण को कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है. दरअसल, पेट्रोल वाली बाइक से इलेक्ट्रिक वाहन पर जाना ऑपरेटरों के लिए इतना आसान नहीं होगा. ऐसे में इन नियम लागू करने के लिए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पद सकता है. इसके लिए नई बाइक खरीदने का खर्च, चार्जिंग स्टेशन की उपलब्धता, बैटरी बदलने की सुविधा और समय पर मरम्मत जैसी व्यवस्थाएं जरूरी होंगी. महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी ऑपरेटरों को पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों पर शिफ्ट होने के लिए जुलाई 2027 तक यानी नौ महीने की समय सीमा दी गई है. इसके तहत अब कंपनियों को अपने बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को पहले मुकाबले ज्यादा बढ़ाने की तैयारी करनी होगी.

इतिहास रचने की दहलीज पर फखर जमन

नई दिल्ली। श्रीलंका क्रिकेट टीम पाकिस्तान दौरे पर है, जहां अभी दोनों के बीच टी20 सीरीज चल रही है. मेजबान पाकिस्तान ने पहले मैच में जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई हुई है, दूसरे टी20 को जीतकर टीम सीरीज में अजेय बढ़त बनाना चाहेगी. श्रीलंका आज जीतकर सीरीज बराबर करना चाहेगी, अगर ऐसा हुआ तो तीसरा मैच निर्णायक बन जाएगा. आज फखर जमन एक छक्का लगाकर इतिहास रच सकते हैं. पाकिस्तान बनाम श्रीलंका दूसरा टी20 आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. पिछले मैच में पाकिस्तान ने 4 विकेट से जीत दर्ज की थी. श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 182 रन बनाए थे. पाक टीम ने लक्ष्य को 7 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया. कप्तान साहिबजादा फरहान ने 89 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी. फखर जमन ने उस मैच में 13 गेंदों में 21 रन बनाए थे. टी20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में फखर जमन पहिले नंबर पर हैं, जिन्होंने 121 मैचों में खेली 111 पारियों में 99 छक्के लगाए हैं. एक छक्का लगाकर वह पाकिस्तान के लिए 100 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन जाऐंगे.

हसन मेहमूद ने ली हैट्रिक

नई दिल्ली। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक मात्र टेस्ट मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले के तीसरे दिन बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हसन मेहमूद ने कमाल की बॉलिंग कर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया है। दरअसल, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले वे बांग्लादेश के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। बांग्लादेश की पहली पारी के 346 रन के जवाब में अफगानिस्तान की टीम 240 रन पर ऑलआउट हो गई। इस तरह बांग्लादेश ने पहली पारी के आधार पर 106 रन की बढ़त हासिल कर ली। इस बढ़त में हसन मेहमूद की घातक गेंदबाजी का अहम योगदान रहा। हसन मेहमूद ने दूसरी नई गेंद से शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने अफगानिस्तान की पहली पारी के 83वें ओवर की तीसरी, चौथी और पांचवीं गेंद पर क्रमशः इस्मत आलम, फैस अहमद और जिया उर रहमान को आउट किया।

रणजी ट्रॉफी में टीम इंडिया के बड़े-बड़े धुरंधर हुए फेल



नई दिल्ली। रणजी ट्रॉफी के नए सीजन में भारतीय टीम के खिलाड़ियों की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही. टीम इंडिया के ओपनर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल घरेलू क्रिकेट में बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे. जायसवाल बिना खाता खोले आउट हो गए, जबकि राहुल सिर्फ 4 रन ही बना सके. दोनों बल्लेबाजों का जल्दी आउट होना उनकी टीमों के लिए बड़ा झटका रहा. मुंबई की तरफ से खेलने उतरे यशस्वी जायसवाल चंडीगढ़ के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में अपना खाता भी नहीं खोल सके. वो 13 गेंद खेलने के बाद आउट हो गए. जायसवाल को वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया था, लेकिन उन्हें तीनों मैचों में खेलने का मौका नहीं मिला था. अब रणजी ट्रॉफी में भी उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही.

केएल राहुल भी नहीं दिखा सके दम

कर्नाटक की तरफ से खेलने वाले केएल राहुल भी आंध्र प्रदेश के खिलाफ सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए. आंध्र के गेंदबाज कवुरी साई तेजा और केवी सासिकांत ने शुरुआती विकेट लेकर कर्नाटक की मुश्किलें बढ़ा दीं. टीम ने शुरुआती 4 विकेट गंवा दिए और बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ गया.राहुल ने इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार बल्लेबाजी की थी. उन्होंने अपनी एकमात्र पारी में 82 गेंदों पर बिना आउट हुए शतक लगाया था. भारत ने ये सीरीज 2-1 से जीती थी. ऐसे में रणजी ट्रॉफी में उनका जल्दी आउट होना निराशाजनक रहा.

जायसवाल की विकेटकीपिंग की चर्चा

मुंबई के कप्तान सिद्धेश लाड के मुताबिक, जायसवाल भविष्य में मुंबई या भारतीय टीम के लिए विकेटकीपिंग करने के बारे में सोच सकते हैं. लेकिन, लाड ने यह भी कहा कि उन्हें जायसवाल की योजना के बारे में पूरी जानकारी नहीं है. मुंबई के शुरुआती मुकाबले से पहले जायसवाल अभ्यास मैच में विकेटकीपिंग करते नजर आए थे.

न्यूजीलैंड सीरीज पर भी रहेगी नजर

राहुल, जायसवाल, वॉशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल उन 11 टेस्ट खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 अनौपचारिक टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए चुना गया है. सीरीज का पहला मुकाबला 24 अक्टूबर से लैंकन में खेला जाएगा. इसके बाद काइस्टर्चर्च और लैंकन में 2 और मैच होंगे. वहीं, भारत की न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी. दोनों सीरीज के कार्यक्रम में टकराव होने के वजह से अगर राहुल, जायसवाल और वॉशिंगटन को सीनियर टीम में जरूरत पड़ती है, तो उनकी उपलब्धता पर असर हो सकती है.

तीसरे वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, गेंदबाजों ने कराया कमबैक

नई दिल्ली।पुडुचेरी में खेले गए तीसरे वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 49 रनों से हरा दिया है. हालांकि, तीसरे वनडे में हार के बाद भी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की, क्योंकि कंगारूओं ने पहले दोनों वनडे में जीत दर्ज की थी. यह सीरीज इंडिया-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच खेली गई. तीसरे अनऑफिशियल वनडे में भारत की ए टीम 47.3 ओवर में 275 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. इंडिया-ए के लिए प्रियांश आर्या ने 45 गेंद में 49, प्रभसिमरन सिंह ने 34 गेंद में 39, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 33 और अंत में सूर्याश शेड्गे ने 60 गेंद में 66 और निपरज निगम ने 44 गेंद में 40 रनों की पारी खेली.



276 रन चेज करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर एक समय 27वें ओवर में दो विकेट पर 140 रन था. ऐसा लग रहा था कि कंगारू टीम क्लीन स्वीप दे देगी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने बाजी पलट दी, और ऑस्ट्रेलियाई टीम 46.2 ओवर में 226 रनों पर ढेर हो गई. इस तरह टीम इंडिया ने 49 रनों से जीत दर्ज की. लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को जोश फिलिप्स और लियाम स्कॉट ने शानदार शुरुआत

दिलाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए 82 रनों की साझेदारी की. स्कॉट 26 रन बनाकर आउट हुए. वहीं फिलिप्स ने 48 गेंद 56 रनों की पारी खेली।

फील्डिंग में टीम इंडिया का बुरा हाल!

नई दिल्ली। टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय टीम की फील्डिंग चिंता का विषय बनती जा रही है। बल्लेबाजी और गेंदबाजी में दम दिखाने वाली टीम इंडिया कैच पकड़ने के मामले में लगातार संघर्ष करती नजर आ रही है। साल 2025 से अब तक के टी20



इंटरनेशनल मुकाबलों के आंकड़े इस समस्या को उजागर करते हैं। क्रिकेट वेबसाइट 'क्रिकबज' की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, भारतीय टीम ने इस अवधि में कई अहम मौकों पर गलतियां की हैं। छोटे फॉर्मेट में फील्डिंग की ऐसी चूक टीम के प्रदर्शन और मैच के नतीजे पर भारी पड़ सकती है।

50 मैचों में 79 कैच छोड़े

'क्रिकबज' के आंकड़ों के अनुसार, टीम इंडिया ने साल 2025 से अब तक खेले गए 50 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में कुल 79 कैच छोड़े हैं। यह आंकड़ा बताता है कि भारतीय खिलाड़ी कैच लेने के अवसरों को लगातार भुनाने में नाकाम रहे हैं। टी20 क्रिकेट में हर विकेट की अहमियत होती है। ऐसे में कैच छोड़ने से विपक्षी बल्लेबाजों को जीवनदान मिलता है और वे इसका फायदा उठाकर टीम के लिए बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं।

त्यौहार पर संकट: 54% परिवारों की आर्थिक हालत पहले से हुई कमजोर

नई दिल्ली। त्योहारी सीजन में कपड़े, मिठाई और घूमने-फिरने की इच्छा तो है, लेकिन परिवार के बजट की चिंता लोगों के कदम खींच रही है। महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरण, गाड़ी और गहने खरीदने के मामले में लोग ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं। सी वोटर के एक ताजा सर्वे के मुताबिक, 53.6% लोगों का कहना है कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति एक साल पहले के मुकाबले खराब हुई है। वहीं, 11.6% लोगों ने आर्थिक स्थिति सुधरने की बात कही। 28 और 29 सितंबर 2026 को 2,051 लोगों के बीच किए गए इस सर्वे में त्योहारों के दौरान खरीदारी, खर्च, ट्रेवल, पेमेंट के तरीके और घर की मरम्मत जैसे मुद्दों पर लोगों की राय जानी गई। सर्वे के नतीजे बताते हैं कि इस बार त्योहारों पर खर्च करने की इच्छा के साथ-साथ पैसे बचाने की चिंता भी बनी हुई है। सर्वे में शहरी और ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति को लेकर बड़ा अंतर सामने आया है। शहरी क्षेत्रों में 40.6% लोगों ने कहा कि उनके परिवार की आर्थिक हालत पिछले साल के मुकाबले खराब हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कहने वालों की संख्या 59.2% रही। कम आय वाले परिवारों में आर्थिक दबाव ज्यादा दिखाई दिया। इस वर्ग के 63.2% लोगों ने अपनी आर्थिक स्थिति बिगड़ने की बात कही।

रूस के फैसले से क्या सस्ता होगा डीजल?

नई दिल्ली। अगर आप अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर नजर रखते हैं, तो रूस का यह फैसला आपके लिए अहम है. रूस ने डीजल निर्यात पर लगी पाबंदी में कुछ ढील देने का फैसला लिया है. इसका मतलब है कि अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीजल की सप्लाई करना आसान हो सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, यह कदम रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत के बाद उठाया गया है. इस फैसले का खास मकसद विदेशी बाजारों में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने के साथ रूस में घरेलू जरूरतों को भी पूरा करना है. हालांकि, इससे डीजल की कीमत कितनी कम होगी, यह मांग और सप्लाई पर निर्भर करेगा.

रूस का कहना है कि उसके यहां डीजल का उत्पादन घरेलू जरूरतों को पूरा करने के साथ दूसरे देशों को सप्लाई करने में भी इससे मदद मिलेगी. रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक के मुताबिक, सरकार तेल कंपनियों के साथ मिलकर डीजल के निर्यात और सप्लाई की व्यवस्था करेगी.दरअसल, यूक्रेन की ओर से रूसी ऊर्जा



है. रिपोर्टों में अक्टूबर में 3 लाख टन, नवंबर में 5 लाख टन और उसके बाद एक लाख टन डीजल की आपूर्ति के आंकड़े भी सामने आए हैं. हालांकि, इन आंकड़ों और सप्लाई की तारीखों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है. रूस दुनिया के बड़े डीजल निर्यातक देशों में से एक है. ऐसे में अगर रूस दूसरे देशों को ज्यादा डीजल भेजता है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी उपलब्धता बढ़ सकती है. ऐसे में जिन देशों को डीजल की जरूरत है, उन्हें अतिरिक्त आपूर्ति मिलने की उम्मीद है।

फर्जी KYC लिंक ने उड़ाई कपल की नींद, अब SBI ग्राहक को देगा 1.35 लाख

नई दिल्ली। केवाईसी अपडेट करने के नाम पर आने वाला एक मैसेज आपकी जमा-पूंजी पर भारी पड़ सकता है. केरल में एक दंपति के साथ ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें फर्जी लिंक के जरिए बैंक खाते से लाखों रुपये निकलने का आरोप लगा. अब उपभोक्ता आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक को शेष रकम लौटाने और मुआवजा देने का निर्देश दिया है. यह मामला साल 2023 का है, केरल के एक दंपति का भारतीय स्टेट बैंक में बचत खाता था. पति ने बैंक में तीन महीने के लिए 10 लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) भी कराई थी. 7 जनवरी 2023 को जब उन्होंने बैंक के ऐप के माध्यम से अपने क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने की कोशिश की, तो भुगतान नहीं हो सका.इसके बाद उन्हें खाता ब्लॉक होने और केवाईसी अपडेट करने से जुड़ा संदेश मिला. पति के मुताबिक, उन्होंने संदेश में दिए गए लिंक के जरिए अपनी जानकारी भरने की कोशिश की. इसी दौरान उनकी एफडी से चार अलग-अलग ट्रान्जेक्शन में करीब 3.28 लाख रुपये निकल गए. दंपति का कहना था कि उन्होंने अनधिकृत निकासी की जानकारी तुरंत बैंक को दे दी थी. मामले में बैंक के आंतरिक बैंकिंग लोकपाल के हस्तक्षेप के बाद लगभग 2.24 लाख रुपये वापस कर दिए गए।

नई दिल्ली। अगर आप भी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन एक साथ पूरा प्रीमियम चुकाना आपके लिए मुश्किल है, तो अब आप किस्तों में पेमेंट का ऑप्शन चुन सकते हैं. अक्सर मेडिकल खर्च बढ़ने के साथ स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम भी लोगों की बजट पर असर डाल रहा है. ऐसे में लोग अब सालाना प्रीमियम एकमुश्त देने के बजाय हर महीने या तीन महीने में पेमेंट करना पसंद कर रहे हैं.पॉलिसीबाजार के आंकड़ों के मुताबिक, उसके करीब 13% ग्राहक हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम मासिक या तिमाही किस्तों में भरना पसंद करते हैं. इन ग्राहकों के लिए ऑसित सालाना प्रीमियम या EMI की रकम 17,500 रुपये है. हालांकि, ये आंकड़े कंपनी के अपने ग्राहकों से जुड़े हैं, पूरे स्वास्थ्य बीमा बाजार की तस्वीर नहीं दिखाते. ऐसे में आइए जानते हैं कि किस्तों में प्रीमियम भरने का तरीका कैसे काम करता है.

किस्तों में कैसे भर सकते हैं हेल्थ

इंश्योरेंस का प्रीमियम?

हेल्थ इंश्योरेंस में किस्तों के जरिए पेमेंट करने पर आपको पूरी रकम एक साथ चुकाने की जरूरत नहीं, बल्कि आप पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक हर महीने या तय अंतराल पर प्रीमियम जमा कर सकता है.उदाहरण के तौर पर अगर तीन



जहां यह सुविधा पॉलिसीधारकों को कवरेज घटाने या पॉलिसी रेंडर कर देने से रोकती है। इंश्योरेंस रेगुलेटर (IRDAI) द्वारा किस्तों में भुगतान की अनुमति दिए जाने के बाद से बीमा कंपनियों ने भी ऑटो-डेबिट और ई-मैडेंट जैसे आसान डिजिटल विकल्प उपलब्ध कराए हैं।



अंबिकापुर में खुलेगा ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ में वन्यजीव संरक्षण और वनांचल के ग्रामीणों की सुविधाओं के विस्तार की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। वन मंत्री श्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में शनिवार को नवा रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में राज्य वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की पहली बैठक हुई। इसमें अंबिकापुर के संजय पार्क में आधुनिक वन्यजीव ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित करने को मंजूरी दी गई। साथ ही संरक्षित वन क्षेत्रों की 18 ग्रामीण सड़कों के उन्नयन संबंधी प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने की अनुशंसा की गई। वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार वन्यजीव संरक्षण के साथ वनांचल के ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम, घायल वन्यप्राणियों के त्वरित उपचार और वन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अंबिकापुर में प्रस्तावित उपचार केंद्र में मानव-वन्यजीव संघर्ष और दुर्घटनाओं में घायल वन्यप्राणियों के त्वरित बचाव, प्राथमिक उपचार और अल्पकालिक देखरेख की सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं, पीएम जनमन योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भोरमदेव अभयारण्य की 3, इंद्रावती टाइगर रिजर्व की 14 और जशपुर के बादलखोल अभयारण्य की एक सड़क के उन्नयन की अनुशंसा की गई।

सेवा संकल्प अभियान के तहत 35 नौनिहालों का हुआ स्वर्णप्राशन

शहर सत्ता/रायपुर। सेवा संकल्प अभियान माह के अंतर्गत बलरामपुर जिले में बच्चों के स्वास्थ्य और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में रविंद्र प्रताप आंगनबाड़ी केंद्र, बलरामपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग तथा आयुष विभाग के संयुक्त तत्वावधान में स्वर्णप्राशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 35 नौनिहालों को स्वर्णप्राशन कराया गया। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करने के साथ उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के अभिभावकों को स्वर्णप्राशन के महत्व एवं इससे संबंधित जानकारी भी दी गई। जिला आयुष अधिकारी डॉ. अरविंद कुमार शर्मा ने अभिभावकों को संबोधित करते हुए आयुर्वेद में स्वर्णप्राशन के महत्व की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद में इसे बाल्यावस्था के महत्वपूर्ण संस्कारों में माना गया है। इसके माध्यम से बच्चों की स्मरण शक्ति, एकाग्रता तथा रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में सहायता मिलने की मान्यता है। कार्यक्रम में डॉ. अन्नपूर्णा गुप्ता सहित महिला एवं बाल विकास विभाग तथा आयुष विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

शत्रुघन के परिवार को पीएम आवास ने दिया सुरक्षित जीवन

शहर सत्ता/रायपुर। कभी बारिश शुरू होते ही घर की चिंता सताने लगती थी। कच्ची दीवारें, खप्पर की छत और मौसम बदलने के साथ बढ़ती परेशानी के बीच परिवार को सुरक्षित रखने की चिंता बनी रहती थी। रायगढ़ जिले के ग्राम पंचायत बनसिया निवासी श्री शत्रुघन जाटवर के परिवार के लिए यह स्थिति अब बीते दिनों की बात हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मिलने से उनके परिवार को न सिर्फ सुरक्षित छत मिली है, बल्कि अपने घर का सपना भी साकार हुआ है। शत्रुघन बताते हैं कि पहले उनका परिवार कच्चे मकान में रहता था। बारिश के दिनों में घर की स्थिति को लेकर विशेष चिंता रहती थी। तेज बारिश और खराब मौसम में घर और परिवार की सुरक्षा की चिंता बनी रहती थी। ऐसे में पक्के मकान की उनकी उम्मीद प्रधानमंत्री आवास योजना से पूरी हुई। पक्का मकान बनने के बाद शत्रुघन और उनके परिवार के जीवन में बड़ा बदलाव आया है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का रायपुर दौरा रद्द RPF के स्थापना दिवस पर शामिल होने आ रहे थे रायपुर



शहर सत्ता/रायपुर। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का रायपुर दौरा अपरिहार्य कारणों से रद्द हो गया है। उन्हें सोमवार, 12 अक्टूबर को रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के 42वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना था। रेलवे प्रशासन पिछले एक महीने से समारोह और रेल मंत्री के दौरे की तैयारियों में जुटा था। इससे पहले उनका दौरा 9 अक्टूबर को प्रस्तावित था, जिसे बदलकर 12 अक्टूबर किया गया था। राजधानी में होने वाले इस समारोह में रेलवे सुरक्षा, यात्रियों की संरक्षा और रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा के प्रति RPF की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की जानी है। कार्यक्रम में RPF

छत्तीसगढ़ केबिनेट: पूर्व अग्निवीरों को मिलेगी नौकरी आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग होगा

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों के अनुभव और दक्षता का लाभ राज्य की सेवाओं में लेने के उद्देश्य से गृह विभाग में आरक्षक के 36 पदों पर भर्ती की अनुमति दी है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया जाएगा।

पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षक के 36 पदों पर भर्ती

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, गृह विभाग में आरक्षक के कुल 36 पदों पर उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध पूर्व अग्निवीरों की भर्ती की अनुमति दी गई है। इसका उद्देश्य सेना में सेवा दे चुके युवाओं के अनुभव और कौशल का लाभ राज्य की सेवाओं में लेना है। राज्य सरकार पहले ही पूर्व अग्निवीरों के लिए इन पदों पर श्रेणीवार 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर चुकी है। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद निर्धारित रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती का रास्ता साफ हुआ है।

आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलेगा

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके तहत ‘आदिम जाति विकास विभाग’ का नाम बदलकर ‘जनजातीय कार्य विभाग’ किया जाएगा। इस बदलाव के लिए शासन के कार्य आवंटन नियमों में संशोधन किया जाएगा। विभाग के नाम में यह परिवर्तन कैबिनेट के फैसलों में शामिल है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 साल के नेतृत्व पर अभिनंदन प्रस्ताव

बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में लगातार 25 वर्ष पूरे होने पर मंत्रिपरिषद ने अभिनंदन प्रस्ताव भी पारित किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे राष्ट्रसेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और अंत्योदय के सिद्धांतों से जुड़ी यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ में आवास, स्वास्थ्य, राशन, सड़क, रेल, बिजली और अन्य विकास कार्यों को गति मिली है। उन्होंने राज्य की ओर से

विश्वस्तरीय खेल सुविधाओं से तैयार होंगे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी : मुख्यमंत्री



शहर सत्ता/रायपुर। रायपुर। छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता इन प्रतिभाओं को पहचानने, तराशने और उन्हें विश्वस्तरीय प्रशिक्षण एवं आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की है। राज्य सरकार इसी दिशा में योजनाबद्ध रूप से आगे बढ़ रही है। हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाएं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के जोरा में आयोजित सेंथ लेक सिटी और इलेंशियम क्लब्स की साझेदारी घोषणा एवं अनुबंध हस्ताक्षर समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में प्रस्तावित विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स क्लब की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे प्रदेश में खेल संस्कृति को नई मजबूती मिलेगी और युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण एवं खेल



सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर क्लब के संस्थापकों और पूरी टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक श्री पुलेला गोपीचंद का छत्तीसगढ़ में स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय बैडमिंटन को विश्व पटल पर नई पहचान दिलाने में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उनके मार्गदर्शन में अनेक खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव बढ़ाया है। नवा रायपुर में उनकी बैडमिंटन अकादमी की शुरुआत प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए बड़ी उपलब्धि साबित होगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि वे अनुशासन, आत्मविश्वास, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का निर्माण भी करते हैं। खेलों में निवेश वास्तव में हमारी युवा पीढ़ी और प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य में निवेश है।



अब 425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से होगी गन्ने की खरीदी

शहर सत्ता/रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के गन्ना किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए शक्कर कारखानों में गन्ने की खरीदी अब 425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किए जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता की खुशहाली ही समृद्ध छत्तीसगढ़ का आधार है। किसानों को उनकी मेहनत का बेहतर प्रतिफल मिले, खेती लाभकारी बने और किसान परिवार आर्थिक रूप से निरंतर सशक्त हों, इसके लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री साय से आज भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट की। प्रतिनिधिमंडल में संगठन मंत्री श्री मनीष शर्मा, महामंत्री श्री नवीन शेष सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल थे। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव और श्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। भेंट के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रदेश के किसानों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। चर्चा के दौरान गन्ना उत्पादक किसानों के हितों से संबंधित विषय भी प्रमुखता से सामने आया। मुख्यमंत्री ने किसानों की भावनाओं और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर त्वरित पहल की और शक्कर कारखानों के लिए गन्ने की खरीदी 425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से करने का निर्णय लिया। पेराई सत्र 2025- 26 में की गई खरीदी का भुगतान भी बढ़े हुए दर पर किया जाएगा।

जशपुर के सीमावर्ती गांवों में सड़क संपर्क को मिल रही मजबूती

शहर सत्ता/रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले के दूरस्थ एवं सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क को मजबूत करने और आवागमन की सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सिकरिमा से विदुरपुर तक 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क का मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य 89 लाख 53 हजार रुपये की लागत से पूर्ण कर लिया गया है। सड़क के डामरीकरण से क्षेत्र के ग्रामीणों को आवागमन में बड़ी राहत मिली है। विशेष रूप से बरसात के दिनों में होने वाली परेशानियां दूर होने के साथ अब ग्रामीणों को बेहतर सड़क सुविधा का लाभ मिलेगा।

सिकरिमा से विदुरपुर मार्ग की स्थिति खराब होने के कारण ग्रामीणों को लंबे समय से आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। विशेषकर बारिश के मौसम में सड़क की खराब स्थिति के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती थी। इसका असर विद्यार्थियों, किसानों, मजदूरों और स्वास्थ्य सेवाओं सहित अन्य आवश्यक कार्यों के लिए आने-जाने वाले ग्रामीणों पर पड़ता था। अब सड़क का मरम्मत एवं डामरीकरण कार्य पूर्ण होने से ग्रामीणों को सुगम और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। जशपुर जिले का सिकरिमा-विदुरपुर मार्ग ओडिशा राज्य की सीमा से लगे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। सड़क के जीर्णोद्धार से सीमावर्ती गांवों का मुख्य मार्गों से संपर्क बेहतर होगा। इससे ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी। बेहतर सड़क संपर्क से किसानों को अपनी कृषि उपज बाजार तक पहुंचाने तथा



ग्रामीणों को दैनिक जरूरतों के लिए आवागमन करने में भी सहूलियत होगी। इसके साथ ही क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

सिकरिमा से विदुरपुर तक सड़क का डामरीकरण कार्य पूर्ण होने से ग्रामीणों को विशेष रूप से बारिश के मौसम में होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी। पहले सड़क की खराब स्थिति के कारण दोपहिया और अन्य वाहनों के आवागमन में कठिनाई होती थी। अब सड़क की स्थिति बेहतर होने से विद्यार्थियों को विद्यालय आने-जाने, मरीजों को स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचने तथा ग्रामीणों को आवश्यक कार्यों के लिए आवागमन करने में सुविधा होगी।

सड़क पर मवेशी, हेल्पलाइन पर शिकायतें और सिस्टम की सुस्ती!

1962 से 1100 तक शिकायतों के बाद भी स्थायी समाधान का इंतजार

रायपुर में
आवारा
पशुओं की
समस्या पर
उठे गंभीर
सवाल

विशेष संवाददाता/विकास यादव

रायपुर। शहर की सड़कों पर घूमते और बीच सड़क पर बैठे मवेशी अब केवल यातायात में बाधा नहीं, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ी गंभीर समस्या बनते जा रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं का खतरा, पशुओं के घायल होने की आशंका और शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं मिलने की स्थिति ने नगर निगम, पशुपालन विभाग तथा प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। डीडी नगर के सेक्टर-2 सहित रायपुर के विभिन्न इलाकों से सामने आई शिकायतें बताती हैं कि समस्या केवल मवेशियों को सड़क से हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके स्थायी प्रबंधन और विभागीय जवाबदेही से भी जुड़ी है। एक ओर घायल और बीमार पशुओं के उपचार के लिए संचालित हेल्पलाइन 1962 तथा मोबाइल वेटरनरी यूनिट की मौके पर पहुंचने की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सड़क से मवेशियों को हटाने के लिए दर्ज शिकायतों के निराकरण में देरी की बात सामने आई है। शिकायतों के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं होने के बावजूद यदि नागरिकों को समय पर सहायता नहीं मिलती, तो इन व्यवस्थाओं की उपयोगिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

डीडी नगर सेक्टर-2 से नए रायपुर तक सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा; कहीं मोबाइल वेटरनरी यूनिट की पहुंच पर सवाल, तो कहीं शिकायतों के निराकरण में 47 दिन तक की देरी का दावा

1962 पर कॉल, फिर भी मौके पर नहीं पहुंची मोबाइल वेटरनरी यूनिट?

घायल, बीमार और दुर्घटना का शिकार हुए पशुओं को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से टोल-फ्री हेल्पलाइन 1962 और मोबाइल वेटरनरी यूनिट की व्यवस्था संचालित है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, रायपुर में चार मोबाइल वेटरनरी यूनिट संचालित होने की जानकारी दी गई थी। इसके बावजूद कुछ मामलों में बार-बार कॉल करने पर भी टीम के मौके पर नहीं पहुंचने की शिकायत सामने आई। एक मामले में गाय के पेट में बड़ा घाव होने की बात सामने आई। बताया गया कि संबंधित व्यक्ति ने सुबह लगभग 10 बजे हेल्पलाइन पर संपर्क किया। पशु चिकित्सा विभाग में भी संपर्क करने के बावजूद तत्काल सहायता नहीं मिलने का आरोप है। रिपोर्ट के अनुसार, दोबारा संपर्क करने के बाद भी गाय को समय पर उपचार नहीं मिल सका और बाद में उसे छोटे हाथी वाहन से पशु अस्पताल ले जाना पड़ा। इस घटना ने व्यवस्था की कार्यक्षमता पर सवाल खड़े किए हैं। यदि किसी घायल पशु को उपचार के लिए अस्पताल तक पहुंचाने में स्थानीय लोगों को ही व्यवस्था करनी पड़े, तो मोबाइल वेटरनरी यूनिट के संचालन, कॉल रिसॉन्स और शिकायतों की निगरानी की समीक्षा आवश्यक हो जाती है।

निदान 1100 पर शिकायत, निराकरण में 47 दिन तक की देरी का आरोप

नगर निगम से जुड़ी शिकायतों के लिए संचालित निदान 1100 व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे हैं। उपलब्ध रिपोर्ट में शिकायतों के निराकरण में देरी का उल्लेख करते हुए बताया गया कि कुछ मामलों में शिकायत दर्ज होने के बाद लंबे समय तक समाधान नहीं हुआ। एक शिकायत के संबंध में 19 अगस्त को शिकायत दर्ज किए जाने और 5 अक्टूबर को लोकेशन पृष्ठने के लिए कॉल आने की जानकारी सामने आई। इस मामले में शिकायत दर्ज होने और बाद में संपर्क किए जाने के बीच लगभग 47 दिन का अंतर बताया गया है। यह अंतर शिकायत के पंजीकरण और उसके प्रभावी निराकरण के बीच की स्थिति की जांच करने की जरूरत दर्शाता है। हालांकि, किसी शिकायत पर बाद में कॉल आना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि पूरे समय कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसकी वास्तविक स्थिति जानने के लिए

